

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 649वीं बैठक दिनांक 07/06/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9919/2023 Noorjahan Bee, Lessee, R/O -177 Hira Colony Captain Hira Singh Marg, Mahidpur, District-Ujjain (MP) Prior Environment Clearance for Delchibujurg Stone Quarry for Gitti & M-Sand in an area of 2.00 Ha. (Stone (Gitti) - 6000 m³/year & M-Sand – 14000 m³/year) at (Khasra No. 748,751 (Private) Village DELCHI BUZURG Tehsil Mahidpur District Ujjain (M.P.)

This is case of Stone Quarry for Gitti & M-Sand. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 748,751 (Private) Village DELCHI BUZURG Tehsil Mahidpur District Ujjain (M.P.) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/06/23 को परियोजना प्रस्तावक नूरजहां बी ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 626 दिनांक 10/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है। आवंटित खदान के पश्चिम दिशा में 42 मीटर पर एवं पूर्व दिशा में 420 मीटर पक्का रोड़ है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ दिख

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

रहे हैं, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पश्चिम दिशा में 42 मीटर पर कच्चा रोड़ है एवं जहां पेड़ है वहां 12 मीटर का नॉन माईनिंग जोन जिसे सरफेस मेप में दर्शाया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल ने पत्र क्रमांक 626 दिनांक 10/03/23 के द्वारा सूचित किया है कि जिले की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2022-23 में बनी है, तत्पश्चात् उक्त पत्थर क्वेशर उत्खनिपट्टा अनुमति प्रदान की गई है । नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 6,000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम. सेंड – 14,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 21.91 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.64 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम डेलची बुजुर्ग के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर दिए जायेंगे	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	600
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	800
3.	ग्राम डेलची बुजुर्ग के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल आदि (पूर्ण सुरक्षा)	200
4.	ग्रामीणों में वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	800
योग			2400

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

2. Case No 9902/2023 Ms. Priyanka Sharma, Lessee, R/o Subhash Marg, Tehsil-Khachrod, District-Ujjain (MP)-456224, Prior Environment Clearance for Chirola Stone and M-Sand Quarry in an area of 1.35 ha. (Stone – 7,000 cum per annum and M- Sand – 13,000 cum per annum) (Khasra No. 654), Village-Chirola, Tehsil-Khachrod, District-Ujjain (MP)

This is case of Stone Quarry for Gitti and M-Sand. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 654), Village-Chirola, Tehsil-Khachrod, District-Ujjain (MP) 1.35 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/06/23 को परियोजना प्रस्तावक प्रियंका शर्मा ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 954 दिनांक 12/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है। आवंटित खदान का उत्तर-पश्चिम दिशा में 132 मीटर पर एवं दक्षिण दिशा में 313 मीटर पक्का रोड़ है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया किसी प्रकार की ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने शपथ-पत्र प्रस्तुतीकरण में दिया गया था। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, खदान के दक्षिण-पूर्व की ओर खदान से लगे हुए 02 से 03 शेड दिखाई दे रहे हैं इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ये शेड शासकीय भूमि पर बने हैं जो कि वर्तमान भू-स्वामी द्वारा श्रमिकों के आश्रय स्थल के रूप में उपयोग करेंगे। खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा में 385 मीटर की दूर पर बिरली आबादी दिखाई दे रही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन ने पत्र क्रमांक 954 दिनांक 12/04/22 के द्वारा सूचित किया है कि जिले की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट 2022-23 में बनी है, तत्पश्चात् उक्त पत्थर केशर उत्खनिपट्टा को अनुमति प्रदान की गई है। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 7,000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम. सैंड – 13,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.86 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.49 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम चिरोल के आंगनवाड़ी में शौचालय एवं पानी की टंकी का निर्माण किया जायेगा	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1660 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, गुग्गल, सफेद कस्टार, सिस्सु, सफेद और कला मिरस आदि।	360
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कुसुम (30%) कदम, चिरोल, आदि	300
3.	ग्राम चिरोल के शासकीय विद्यालय, ग्राम पंचायत परिसर में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कुसुम कदम, चिरोल, कटहल आदि (पूर्ण सुरक्षा)	400
4.	ग्राम चिरोल के रामदेव बाबा मंदिर में	तुलसी, कदम, उतरन जीवा, बेल, पीपल, बरगद आदि	200
5.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	200
योग			1660

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

3. Case No 9901/2023 Shri Sanjeev Sharma, Owner, R/o D/2/001, Windsor Hills, New City Centre, Sirol, District-Gwalior (MP)-474001, Prior Environment Clearance for Gadajar Flagstone Quarry in an area of 2.585 ha. (15001 cum per annum) (Khasra No. 64, 65), Village-Garajar, Tehsil-Morena Hal, District- Morena (MP)

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 64, 65), Village-Garajar, Tehsil-Morena Hal, District- Morena (MP) 2.585 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 649वीं बैठक दिनांक 07/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

4. प्रकरण क्रमांक 8929 / 2022 –श्री जीवन चौधरी, ग्राम कल्यांसीखेडी तहसील पीथमपुर जिला धार (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 168/6, 168,7/1, 168/7/2, 168/11 रकबा 2.80 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन-19000 मी.³, वेस्ट – 1000 मी.³, मुरुम एज ओवर –12,000 मी.³, ग्राम कल्यांसीखेडी तहसील पीथमपुर जिला धार के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा ऑनलाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 168/6, 168,7/1, 168/7/2, 168/11 पेकी रकबा 2.80 हेक्टेयर, ग्राम कल्यांसीखेडी तहसील पीथमपुर जिला धार .प्र. पर स्थित है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 549वीं दिनांक 15/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 07/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन चौधरी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर खदान स्थल के दक्षिण दिशा में 20 मीटर पर कच्चा रोड़ होना परिलक्षित होता है एवं खदान के उत्तर-पूर्वी की ओर एक शेड स्थित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह सर्वजानिक/आम रास्ता नहीं है बल्कि हॉलेज रोड़ है । खदान के बैरियर जोन में 02 पेड़ हैं जो काटे नहीं जावेगे।

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

खदान के उत्तर-पूर्वी की ओर एक शेड है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह श्रमिकों के अश्राय स्थल है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-48 के सरल क्रमांक-1 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान क्षेत्र एवं स्टडी एरिया का विंडरोज डाईग्राम ।
2. प्रस्तुतीकरण के समिति ने पाया कि वायु मापन के दौरान पी.एम. 2.5 की वैल्यू कम प्रतीत हो रही है, अतः म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धार के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पी.एम. 2.5 की वैल्यू शुल्क के आधार पर पुनः मानिट्रिंग की जावे ।

5. प्रकरण क्रमांक 9036/2022 - श्री जीवन रघुवंशी, ओनर, ग्राम अकोलिया तहसील एवं जिला धार (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1022/1/जी/2पेकी, रकबा 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन-14,550 मी.³, ग्राम खेड़ा तहसील एवं जिला धार (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1022/1/जी/2 पेकी, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम खेड़ा तहसील एवं जिला धार (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 556वीं दिनांक 02/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 07/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन रघुवंशी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । खदान निजी भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 300 मीटर पर क्लीकल टेंसिटिंग फेसिलिटी है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस दिशा में किसी मिनरल का परिवहन नहीं किया जायेगा खदान के दक्षिण दिशा में प्रतिबंधित क्षेत्र में 3 लाइनों में 4 फीट लम्बाई के पौधे लगाए जायेंगे खदान में कंट्रोल ब्लास्टिंग की जाएगी ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-20 के सरल क्रमांक-36 पर दर्ज है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान क्षेत्र एवं स्टडी एरिया का विंडरोज डाईग्राम ।
2. प्रस्तुतीकरण के समिति ने पाया कि वायु मापन के दौरान पी.एम. 2.5 की वैल्यू कम प्रतीत हो रही है, अतः म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धार के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पी.एम. 2.5 की वैल्यू पुनः सत्यापित कर प्रस्तुत करे ।

6. Case No 9272/2022 Shri Hari Singh Raghuwanshi, Owner, Village - Khandwa, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, MP Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone Gitti - 25000 cum per annum, Murrum - 20000 cum per annum) (Khasra No. 646/2, 647 Peki) Village - Khandwa, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, (MP)

This is case of Stone & Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 646/2, 647) Village - Khandwa, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 587वीं दिनांक 02/08/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 07/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हरि सिंह रघुवंशी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । खदान निजी भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 130 मीटर, पश्चिम दिशा में 100 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा उत्तर-पूर्वी दिशा में 770 मीटर पर तालाब है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तावित खनन पट्टे के उत्तर दिशा में जलाशय को जोड़ने वाली सड़क पर 1200 मीटर तक की लम्बाई पर सड़क के दोनों तरफ 2 लाइनों में 1200 पौधे लगाए जायेंगे एवं जलाशय के निकट लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में तार बंदी के साथ 2200 पौधे लगाए जायेंगे इस संबंध में समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि जलाशय के जहां पौधा रोपण किया जाना है, इसके लिये पौधारोपण के पूर्व सिचाई विभाग/ग्राम पंचायत से सलाह/अनुमति प्राप्त कर लेवे । एवं संरक्षण हेतु गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये । साथ ही

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

प्रश्नाधीन खदान में 07 पेड़ लगे दिख रहे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ये 07 पेड़ काटा जाना प्रस्तावित है इसके एवज में 70 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-48 के सरल क्रमांक-3 पर दर्ज है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान क्षेत्र एवं स्टडी एरिया का विंडरोज डाईग्राम ।
2. प्रस्तुतीकरण के समिति ने पाया कि वायु मापन के दौरान पी.एम. 2.5 की वैल्यू कम प्रतीत हो रही है, अतः म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धार के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पी.एम. 2.5 की वैल्यू पुनः सत्यापित कर प्रस्तुत करे ।

7. Case No 9907/2023 Shri Kapil Patel, Lessee, R/o 103/1, Rapat Road, Jaora, District-Ratlam (MP)-457226, Prior Environment Clearance for Rojana Stone Quarry in an area of 1.998 ha. (7600 Cum per annum) (Khasra No. 17/1), Village-Rojana, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 17/1), Village-Rojana, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP) 1.998 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री कपिल पटेल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन.सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 918 दिनांक 28/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है खदान का कुछ भाग उत्तरी ओर में खुदा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें जल भराव है, खदान की पूर्वी सीमा में 13 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रोड़ निकल रहा है एवं खदान के अंदर दक्षिणी ओर एक केशर लगा हुआ दिख रहा है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया यह ई.सी. हस्तान्तरण का प्रकरण है जिसमें कि पूर्व में उक्त खदान की पर्यावरण स्वीकृति डिया से

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

हुई थी। समिति ने परीक्षण के दौरान डिया से प्रदत्त पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का (वृक्षारोपण एवं सीईआर) का अनुपालन नहीं पाया गया अतः सिया स्तर से जिलाध्यक्ष को इस संबंध में सूचित किया जाना प्रस्तावक है। दक्षिणी सीमा में खदान के अंदर कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं अतः परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र में स्थित पेड़ों की इन्वेन्ट्री ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-18 के सरल क्रमांक-4 पर दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. डिया से प्रदत्त पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का (वृक्षारोपण एवं सीईआर) का अनुपालन ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. खदान का कुछ भाग उत्तरी ओर में खुदा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें जल भराव है, खदान की पूर्वी सीमा में 13 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः परियोजना प्रस्तावक इसके संरक्षण की योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत करें।
3. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिणी सीमा में खदान के अंदर कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं अतः परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र में स्थित पेड़ों की इन्वेन्ट्री ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

8. Case No 9906/2023 Shri Thakur Vinay Bahadur Singh, Proprietor, M/s Sisodia Minings Private Limited, R/o Satendra Bhavan Bhatta Mohalla, Tehsil & District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Bhatgawan-Sunehara Limestone & Dolomite Mine in an area of 17.44 ha. (Expansion from 7045 TPA to Limestone-87600, Dolomite-11607 Tonne per annum) (Khasra No. 213/2, 214/258, 211, 213/1), Village- Bhatgawan-Sunehara, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP)

This is case of Limestone & Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 213/2, 214/258, 211, 213/1), Village-

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

Bhatgawan-Sunehara, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP) 17.44 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री ठाकुर विनय बहादुर सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन.सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3501 दिनांक 30/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है खदान के अंदर लगभग 30 पेड़ लगे हैं (परिवेश पोर्टल पर) जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए हैं, खदान की पूर्वी सीमा से आबादी/मकान लगे हुए दिख रहे हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक इसके संरक्षण की योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत करें। उक्त खदान को पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 25/5/11 को जारी हुई जिसके अंतर्गत परियोजना प्रस्तावक को 1000 पेड़ प्रथम वर्ष में एवं 5000 पोधे प्रथम वर्ष से पांच वर्ष के अंदर लगाये जाने थे।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21 के सरल क्रमांक-62 पर दर्ज है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों जैसे पौधारोपण एवं सी.ई.आर. सहित अन्य शर्तों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पालन प्रतिवेदन, ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के अंदर लगभग 30 पेड़ लगे हैं (परिवेश पोर्टल पर) जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए हैं, खदान की पूर्वी सीमा से आबादी/मकान लगे हुए दिख रहे हैं इसके संरक्षण की योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत करें।
3. प्रश्नाधीन खदान का पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः अन्य शर्तों के साथ वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि भू-जल का प्रतिष्ठेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

9. Case No 9911/2023 Shri Anil Malviya, PP, House No. 06, Bhawani Nagar, Indrapuri, District-Bhopal (M. P.)-462022, Prior Environment Clearance for Khadampur Stone & M-sand Quarry in an area of 3.997 ha. (Stone-46500, M-sand-31000 Cum per annum) (Khasra No. 177/4) Village- Khadampur, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP)

This is case of Stone & M-sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 177/4) Village- Khadampur, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP) 3.997 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल मालवीया (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुजम्मिल खान, (ऑनलाईन) मेसर्स इन-सीटू इन्वायरो केयर, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1291 दिनांक 14/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है खदान के दक्षिण-पूर्वी दिशा में 14 मीटर पर एवं उत्तर दिशा में 289 मीटर में एक पक्का रोड़ है उत्तर दिशा में 296 मीटर की दूरी पर आबादी है । इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी दिशा में 14 मीटर पर पक्का रोड़ नहीं कच्चा रोड़ है । अन्य संवेदनशील बिंदुओं के बारे में परियोजना प्रस्तावक इसके संरक्षण की योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत करें । खदान के अंदर कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं अतः परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र में स्थित पेड़ों की इन्वेन्ट्री ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल ने पत्र क्रमांक 1291 दिनांक 11/04/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है । नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 40 के सरल क्रमांक- 101 पर दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के दक्षिण-पूर्वी दिशा में 14 मीटर पर एक पक्का रोड़ है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी दिशा में 14 मीटर पर पक्का रोड़ नहीं कच्चा रोड़ है अतः इस संबंध में संबंधित विभाग से प्रमाणित करवाकर लाये कि दक्षिण-पूर्वी दिशा में 14 मीटर पर पक्का रोड़ नहीं कच्चा रोड़ है ।
2. खदान के उत्तर दिशा में 289 मीटर में एक पक्का रोड़ है उत्तर दिशा में 296 मीटर की दूरी पर आबादी है । अतः परियोजना प्रस्तावक इसके संरक्षण की योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान के 500 मीटर में स्थित अन्य खदानों की गई तार फेंसिंग की जानकारी ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन के अंदर कुछ पेड़ लगे हुए हैं अतः परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र में स्थित पेड़ों की इन्वेन्ट्री (उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth) ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

10. Case No 9912/2023 Smt. Pramila Sharma, Director, House No. -8, 5 Vinay Grah, Nirman Society Hoshangabad Road, Jatkhedhi, Tehsil Huzur, Distt. – Bhopal (M.P.). 462026. Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility at Survey No - 36/5 ,Village Tutipura, Tehsil & District Rajgarh, Madhya Pradesh , Total Plot Area - 1.38 Acres (5610sq.m) Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.

This is a case of Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatment Facility at Survey No - 36/5 ,Village Tutipura, Tehsil & District Rajgarh.

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

The proposed project is for setting up of common bio-medical waste treatment facility and project falls under Category “B” Projects of activity 7(da) as per EIA Notification dated 14th September, 2006 and its subsequent amendments under Bio- Medical Waste Treatment Facilities. The online application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal and necessary recommendations.

The case was presented by Environment Consultant Dr. Draksha Gupta, M/s. Shivalik Solid Waste Management Limited, Dhakoli, Zirakpur, Punjab and PP Smt. Pramila Sharma, Director on dated 07/06/23 wherein PP stated that proposed Common Bio Medical Waste Treatment Facility involves collection, Transportation, storage and treatment of Biomedical waste from health care facilities and this proposed project is for temporary storage and treatment of Biomedical Waste.

The proposed equipment details are given below:

- 01 incinerator of 200 Kg/hr,
- 01 autoclave of 1000 L/batch, and
- 01 shredder of 100 kg/hr of incinerator
- 01 ETP of 7.5 KLD

PP submitted in the PFR report that presently, the Rajgarh area is being served by M/s J K Medical Waste Management at Godhan, Chanderi, Ashok Nagar which is located at a distance of 170 km. There is no other facility within 75 Km from the proposed site. The proposed facility to be established at Village Tutipura, dist. Rajgarh, MP will cater to the requirement of all HCF in district Rajgarh, surrounding areas covering parts of Guna, Shajapur and Agar-Malwa districts and other nearby districts to be decided by MPPCB which can be approached easily to meet time limit for treatment and disposal of bio-medical waste as stipulated under the BMW Rules (i.e., within 48 hours).

During presentation it was observed by the committee that PP submitted a reply dated 17/04/23 submitted against EDS sought by SEIAA that no wildlife sanctuary / national park exist within 10 km radius of the project and also submitted an Affidavit for no construction activities on the project site has done.

PP stated that water requirement is 09 KLD and source of water is Bore Well. The site is located on private land and on the eastern side of a pucca road at a distance of 17 meters and there are two natural drain are existed one in the South – west side at a distance of 167 meters and another in the in the North – east side . A habitation is existed at a distance of 670 m in the South – East side.

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

As per MPPCB Guidelines for Common Bio-medical Waste Treatment Facilities one district one facility hence PP shall plan only for Rajgarh district.

It was mentioned during the discussion that the no. of beds in Rajgarh district are not sufficient to operate the facility economically, however this is the responsibility of the PP to comply with the SOP.

After deliberations committee decided to recommend standard TOR prescribed by the MoEF&CC may be issued for conducting the EIA with following additional TORs and as per conditions mentioned in Annexure-D:-

- a. Capacity assessment of proposed facility with the existing Bio-medical waste Generation in the EIA report.
- b. As per MPPCB Guidelines for Common Bio-medical Waste Treatment Facilities one district has one facility hence PP shall plan only for Rajgarh district.
- c. PP shall carry out comprehensive gap analysis through data authentication from Government agency and justify their proposal for establishment of another CBWTF within 75 kms radius.
- d. Facility should be developed in accordance with the provisions made in the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by GOI and Guidelines published by CPCB & MPPCB for Common Bio-medical Waste Treatment Facilities.
- e. Thus PP shall justify their site selection & location criteria as per clause 6(b) of CPCB Guidelines for Common Bio-medical Waste Treatment & Disposal Facility with all sensitive's features.
- f. Since 9.0 KLD ground water abstraction is proposed, the permission from CGWB shall be submitted with EIA report .
- g. PP shall carry out comprehensive gap analysis through data authentication from Government agency and justify their proposal for establishment of another CBWT facility within 75 Kms.
- h. Land use – diversion (if any) documents shall be submitted with EIA report.
- i. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report.
- j. Detailed Water balance shall be submitted with EIA report.
- k. Elaborate in the EIA report considering that the proposed technology is “Best Available Technology” of CBWTF.
- l. Plume Dispersion modelling study wrt nearby habitations shall be carried out and result discussed in the EIA report shall be conducted.
- m. Justify in EIA report, how unit will remain zero discharge.

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

- n. Disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
- o. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.
- p. Maximum storage time of Bio-medical waste within the facility and disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
- q. Monitoring of VOC should be added in the proposed monitoring protocol of EIA study.
- r. Proposal for GPS enable vehicles and their route maps shall be discussed in the EIA report.
- s. Elaborate handling and disposal of hazardous waste and possible spillage avoidance in the EIA report.
- t. Ash storage and sharp pit design criteria shall be discussed in the EIA report.
- u. If any case is under consideration in any court of law with respect to this facility, same shall be reported/decision taken by court of law (orders/judgments) with its chronology till date in EIA report.

11. Case No 9834/2023 Shri Manish Asati, Project Director, National Highways Authority of India Indore, 15 Sampat Hills, Opp. Sahara City, Indore Bypass, Indore (MP)-452016, Prior Environment Clearance for Construction of Multi Model Logistics Park (MMLP) in an area of 103.26 ha. at Khasra No. Village-Kheda, Jamodi & Akolia, Tehsil-Pithampur, District-Dhar, (MP).

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Multi Model Logistics Park Mine in an area of 103.26 ha. at Khasra No. Village-Kheda, Jamodi & Akolia, Tehsil-Pithampur, District-Dhar, (MP) .Cat. - 8(b) Township and Area Development Projects.

प्रकरण आज सेक की 641वीं बैठक दिनांक 03/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

The case was presented by DPR Consultant M/s. Feedback Infa Private Limited Shri Navneet Kumar (online), National Highways Authority of India Indore. Wheein PP submitted that the proposed project is development of Multi Modal Logistic Park at villages Kheda, Jamodi and Akolia in Pithampur Tehsil in Dhar district of Madhya Pradesh. PP submitted following salient features of the proposed project:

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

- Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA), Govt. of India has approved 35 MMLPs locations across the country for development of Multi Modal Logistics Park (MMLP) to boost the multimodal transport in India.
- Indore is one of the location approved location for development of MMLP.
- The proposed project site is located at Kheda, Jamodi & Akolia villages of Pithampur Tehsil in Dhar district
- The development of MMLP is proposed in DBFOT basis
- State Govt. (Govt. of MP) is providing the land for development of MMLP, NHAI through NHLML is providing external 4 lane connecting road, Water supply, Power supply. Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) is responsible for providing rail connectivity to the site.
- The proposed MMLP project will facilitate the efficient, cost-effective and value-added total logistics services like cargo aggregation/ disaggregation, distribution, inter modal transfer, light manufacturing, sorting, packing, re-packing. Custom clearance *etc* in the project area.
- It is well connected via road and rail and has excellent accessibility from the nearby markets / industrial growth centers.

PP further submitted that Multi Modal Logistics Parks (MMLPs) are conceptualized to enable seamless intermodal freight/cargo movement and offer multiple functional benefits and services to users. The features of an MMLP facility are-

- Min. area of 100 acres
- Rail, Port/Airport connectivity
- Higher cargo volumes
- Logistics services like Aggregation, Processing, Assembling, Storage & Distribution

Objective of the MMLP

- Reduction in logistics cost from 14% to less than 10% of GDP at par with international standards.
- Transportation cost reduction: Expected to drive cost reduction in transportation cost by enabling freight movement on higher sized trucks and due to modal shift from road to rail for long haul movements.
- Pollution reduction: MMLPs reduce pollution by decreasing the number of vehicle trips, shift of freight movement to higher sized trucks and rail.

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

- Congestion reduction: The decreased number of vehicle trips and modal shift from road to rail is likely to reduce congestion on road. In addition, shifting warehouses and distribution centers, currently being operated inside the city, to these logistics parks would free up urban spaces, enabling congestion reduction.
- It will promote hub and spoke model of transport network compared to point-to-point network.
- It is expected to lower handling costs due to presence of best in class modern and mechanized handling infrastructure.
- MMLPs benefit from economies of scale, by creating shared infrastructure and due to availability of more options for selection of competitive and reliable logistics providers.

Salient Features

PARTICULARS	DETAILS
Project Activity	8(b) Townships/Area Development Project
Category	Category B1 (area > 50 ha.)
Project Details	
Name of Project	Multi Modal Logistic Park (MMLP) at villages Kheda, Jamodi and Akolia in Pithampur Tehsil in Dhar district of Madhya Pradesh
Location	Kheda, Jamodi and Akolia villages of Pithampur Tehsil in Dhar district of Madhya Pradesh
Name of the Proponent	M/s. National Highway Authority of India (NHAI)
Nature of the Project	Greenfield Project
Total Plot Area	103.26 ha (Green Cover ~10.4 ha)
Building Configuration	Warehouses with Rail siding
Waste water generation, treatment and disposal	STP of 560 KLD will be provided, treated water shall be used for horticulture and allied activities
Estimated Project Cost	INR 1111 Cr. (Authority investment (GOI, GoMP & RVNL) Rs. 353 Cr & Private investment (Concessionaire Rs. 758 Cr.)

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

PARTICULARS	DETAILS
Present Land use	Agriculture, Crop land
Eco-sensitive/Protected area	The proposed project neither falling nor having within 10km radius of any ecological sensitive/protected area notified under Wildlife Protection Act 1972
Forest Area	There is no forest land involved in this project
Employment Potential	About 4500 nos. of employment will be generated directly or indirectly.
Water Requirement	Total Water demand is estimated about 1008 kLD (~700 kLD as Fresh Water)
Waste Generated/disposal	Waste will be sent to authorized vendors
Water bodies	RWH Pond is proposed within the project area. Nalla is crossing adjacent to site.
Trees to be translocated	About 45 trees exists. Efforts will be made to maintain the same. In case required. Propriety shall be given for trans location. In extreme casse appropriate authority will be approached for cutting permission withn compensatory plantation. In addition to above, it is proposed to plant 3000 trees of native species in green belt along the project boundary.
Nearest Railway Station	Tihi Railway Station - ~8.2 km Sagore Railway Station - ~6.68 km (Proposed)
Nearest Road	Mhow-Neemuch road (~0.7 km), NH-52 (~9 km) and NH-47 (~16 km)

PARTICULARS	DETAILS
Nearest Airport	Indore Airport, 33km
State, National Boundaries	Nil
Green Energy	Provision of Roof Top Solar panels for day time power requirement with connection to GRID
RWH/Recharge Pit	Pond (1.69Acre) is proposed for RWH in addition to Recharge pits. Water stored in ponds will be used for plantation
Green Belt	5 m green belt shall be developed all along periphery
STP	560 kLD STP with 25 % additional capacity shall be provided with recycling of water for horticulture and allied activities

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

S. No	Site Area for MMLP	Phase-1	Phase-2	Phase-3	Total	Percentage (%)
1.	Site area for MMLP	204473	276382	161951	642806	62.25
2.	Rail Siding and Platform	81744	40316	0	122060	11.82
3.	Office Building	3,358	1,376	0	4734	0.46
4.	Commercial Building	7,809	8,011	5,786	21606	2.09
5.	Residential Building	0	4,371	2,716	7087	0.69
6.	Green Area	20577	83625	0	104202	10.09
7.	Internal Roads	125020	5122	0	130142	12.60
Total Area (Sq.m)		442981	419203	170453	1032637	100.00
Total Area (Acre)		109.46	103.59	42.12	255.17	

After presentation, Committee recommended to issue standard TOR as prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits.
2. Status of land whether agriculture/ vacant land.
3. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
4. Submit ground water recharge plan wrt construction shall be taken in the area.
5. Huge quantity of Soil shall be scrapped before construction hence, soil management plan shall be discussed in EIA report.
6. Green area development for this project shall be proposed upto 12 % and depict green area locations in the EIA report.
7. Proposed development (deepening & expansion work) of existing pond located in the nearby area .
8. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
9. Carbon foot print analysis for proposed production shall be studied and discussed in EIA report.

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

10. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
11. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
12. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
13. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
14. Surface of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
15. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area.
16. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
17. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.

12. Case No 9924/2023 Shri Sumit Pandey, Partner, M/s KRUPA WASTAGES, NEAR GAYATRI TEMPLE, Shastri Ward, Barapatthar, Seoni, M. P. Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility at Plot No.- Plot No 16, Maneri, District - Mandla (M. P.). Proposed project of setting up of the Common Bio-medical Waste Treatment Facility for treatment of 200+100 kg per hour Static kiln-based bio medical incineration project, includes Incinerator, Autoclave, Shredder, Storage and Effluent Treatment Facility. Following will be the capacity of the facility:Capacity – 200 TPA. Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.

This is a case of Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatment Facility at Plot No 16, Maneri, District - Mandla (M. P.). (M.P.).

The proposed project is for setting up of common bio-medical waste treatment facility and project falls under Category “B” Projects of activity 7(da) as per EIA Notification dated 14th September, 2006 and its subsequent amendments dated 17th April 2015, under

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

Bio- Medical Waste Treatment Facilities. Online application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal and necessary recommendations.

The case was presented by Environment Consultant The case was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra and their representatives on behalf of PP Shri Devendra Authorized signatory on dated 07/06/23 wherein PP stated that proposed project of setting up of the Common Bio-medical Waste Treatment Facility for treatment of 200+100 kg per hour Static kiln-based bio medical incineration project, includes Incinerator, Autoclave, Shredder, Storage and Effluent Treatment Facility. Following will be the capacity of the facility:

The Project components comprises as

- 2 Static Kiln 2 Nos. 200
- 2 Autoclave 1+1Nos. 500 Lit/recycle
- 3 Shredder 1+1Nos. 10 0kg/hr.
- 4 Effluent Treatment Plant 1Nos. 7 KLD

MIDC Vide letter no. 6383 dated 14.03.2023 mentioned that 10000 LPD Water will be provided by MP Industrial Development Corporation Ltd. Regional Office Jabalpur from their existing water supply scheme to the proposed project. During discussion It was observed that one another facility has already obtained EC in the same district from **MP SEIAA Case No. - 5394/2016, M/s Medicare Environmental Management Pvt. Ltd., Common Biomedical Waste Treatment Facility (Khasra No. 15 & 17) at Village - Maneri, Teh.- Niwas, Distt. Mandla, MP for which EC was granted in 514 SEIAA meeting dated 14-12-2018. EC issued vide letter no. 2221-22/SEIAA/19 dated 12-02-19. It was come to notice that the EC is valid is till date of this facility. The prevailing policy of MPPCB is one district one CBWTF facility. So in this case the M/s Medicare Environmental Management Pvt. Ltd., if applied for CTE/CTO then its right for installation of facility will be considered on on priority basis.**

It was mentioned during the discussion that the no. of beds in Rajgarh district are not sufficient to operate the facility economically, however this is the responsibility of the PP to comply with the SOP.

After deliberations committee decided to recommend standard TOR prescribed by the MoEF&CC may be issued for conducting the EIA with following additional TORs and as per conditions mentioned in Annexure-D:-

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

- a. Capacity assessment of proposed facility with the existing Bio-medical waste Generation in the EIA report.
- b. As per MPPCB Guidelines for Common Bio-medical Waste Treatment Facilities one district has one facility hence PP shall plan only for Mandla district.
- c. PP shall carry out comprehensive gap analysis through data authentication from Government agency and justify their proposal for establishment of another CBWTF within 75 kms radius.
- d. Facility should be developed in accordance with the provisions made in the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by GOI and Guidelines published by CPCB & MPPCB for Common Bio-medical Waste Treatment Facilities.
- e. Thus PP shall justify their site selection & location criteria as per clause 6(b) of CPCB Guidelines for Common Bio-medical Waste Treatment & Disposal Facility with all sensitive's features.
- f. PP shall carry out comprehensive gap analysis through data authentication from Government agency and justify their proposal for establishment of another CBWT facility within 75 Kms.
- g. Land use – diversion (if any) documents shall be submitted with EIA report.
- h. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report.
- i. Detailed Water balance shall be submitted with EIA report.
- j. Elaborate in the EIA report considering that the proposed technology is “Best Available Technology” of CBWTF.
- k. Plume Dispersion modelling study wrt nearby habitations shall be carried out and result discussed in the EIA report shall be conducted.
- l. Justify in EIA report, how unit will remain zero discharge.
- m. Disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
- n. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.
- o. Maximum storage time of Bio-medical waste within the facility and disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
- p. Monitoring of VOC should be added in the proposed monitoring protocol of EIA study.
- q. Proposal for GPS enable vehicles and their route maps shall be discussed in the EIA report.
- r. Elaborate handling and disposal of hazardous waste and possible spillage avoidance in the EIA report.
- s. Ash storage and sharp pit design criteria shall be discussed in the EIA report.
- t. If any case is under consideration in any court of law with respect to this facility, same shall be reported/decision taken by court of law (orders/judgments) with its chronology till date in EIA report.

13. Case No 9920/2023 Shri RAJA PATEL, Owner, VILLAGE BARDHA, TEHSIL KHURAI, DISTRICT SAGAR (MP) Prior Environment Clearance for Bardha Crusher Stone Quarry in an area of 4.00 Ha. (Stone - 15100 m³/year) at (Khasra No. 575/1 (Govt.) Village KHURAI Tehsil Khurai District Sagar (M.P.)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 575/1 (Govt.) Village KHURAI Tehsil Khurai District Sagar (M.P.) 4.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजा पटेल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीश पटेल, मेसर्स फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एण्ड क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट कंसलटेंसी (एफईसीसीएम) प्रा.लि., भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 328 दिनांक 11/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है खदान के दक्षिण दिशा में 33 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये। खदान के उत्तर पूर्वी दिशा में 54 मीटर एवं 85 मीटर पर लीनियर संरचना दिखाई दे रही है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीनियर संरचना बीजो के संरक्षण हेतु सीड स्टोरेज किये गये हैं। खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में एक नाला है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये। खदान के अंदर कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं अतः परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र में स्थित पेड़ों की इन्वेन्ट्री ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 29 के सरल क्रमांक-18 पर दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के दक्षिण दिशा में 33 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।
2. खदान के उत्तर पूर्वी दिशा में 54 मीटर एवं 85 मीटर पर लीनियर संरचना दिखाई दे रही है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीनियर संरचना बीजो के संरक्षण हेतु सीड स्टोरेज

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

किये गये हैं एवं खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में एक नाला है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये। खदान के अंदर कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं अतः परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र में स्थित पेड़ों की इन्वेन्ट्री ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

3. खदान के अंदर कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं अतः परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र में स्थित पेड़ों की इन्वेन्ट्री ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉपट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

14. Case No 9913/2023 M/s Tata Steel Limited, Head Manufacturing LR PC and Product Factory Manager, Plot No. 158, 158A, Sector-III, Industrial Area, Pithampur, Tehsil & Dist. Dhar, MP for Regularization of Existing Production Facilities for Steel Wires of Capacity 180000 TPA [Seeking EC for regularization of existing CTE Capacity as per NGT Order dtd. 12.02.2020 and MoEFCC, Notification S.O. 3250(E) dtd. 20.07.2022] At Plot No. 158 & 158A, Sector-III, Industrial Area Pithampur, Tehsil & District : Dhar, Madhya Pradesh – 454775 by M/s. Tata Steel Limited Cat. 3(a).

This is case of Prior Environment Clearance for Regularization of existing production facilities for production of Steel Wires (101400 TPA) at Plot No. 158 & 158A, Industrial Area, Pithampur, Dist. Dhar (MP), Category: 3(a).

The case was presented by Env. Consultant Shri Neelanjan Viswas from M/s. Enacon Lab. Pvt. Ltd., Nagpur Mh. & PP Shri Shrikant Vyawhare. PP submitted that the proposal is for a regularization of production facilities for Steel Wires of capacity 180000 TPA (as per valid CTE) located at Plot No. 158 & 158A, Sector-III, Industrial Area Pithampur, Tehsil & District: Dhar, Madhya Pradesh – 454775. This is a proposal for seeking Environmental clearance for regularization of existing production facilities (valid CTE) as per NGT Order dated 12th February, 2020 and MoEFCC, Notification S.O. 3250(E) dtd. 20th July. 2022.

Company has valid CTO available from MPPCB with Consent No. - AWH-57134 dt. 05.12.2022 with validity till 30.11.2023 for capacity of 101400 TPA Moreover, TSL –

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

Pithampur issued CTE (Outward No:-116544,06/10/2022, Consent No: CTE-56785) dtd. 06.10.2022 from MPPCB for production of Steel Wires 1,80,000 TPA. Thus, as per MoEFCC Notification S.O.3250(E) dtd. 20.07.2022, aforesaid environmental clearance proposal for regularization of the capacity of Steel Wires : 1,80,000 TPA.

PP submitted following submission following salient features of the project:

- The company “M/s. TATA Steel Limited - Wire Division” was established in 1975 to produce steel wires for various applications. Wire division is one of the profit centres. The main objective of the organization is to achieve optimum production with high safety health & environment standard.
- “M/s. TATA Steel Limited - Wire Division” Pithampur MP plant started its operations in 2006, its old unit named as Indore Wire Company, acquired by Tata Steel Ltd. PWP as on 2021 is one of the well-established manufacturing unit for GWI from operational, market & financial perspective. PWP has become hub for infrastructure segment. Produces all wires of infra family like LRPC strand, single LR, PCSR etc. and is largest plant by capacity owned by GWI.
- The proposal is for a Regularization of facilities for steel wires of capacity 180000 TPA (as per CTE) located at Plot No. 158 & 158A, Industrial Area Pithampur, District: Dhar (MP) - 454775.
- This is a proposal for seeking Environmental clearance for regularization of existing production facilities (as per CTE) as per MoEFCC, Notification S.O. 3250(E) dtd. 20th July. 2022
- The Company has valid CTE for 180000 TPA production capacity from MPPCB with Letter No. 57134 Dtd. 06.10.2022.
- The present proposal is coming falls under Sector 3(a) Metallurgical Industries of B - Category as per EIA Notification 2006.
- Public Hearing exempted for rolling mills regularization projects As per Gazette of India Notification dtd. 20th July, 2022.

The Committee after deliberations recommends that this is a proposal for seeking Environmental clearance for regularization of existing production facilities (as per CTE) as per MoEFCC, Notification S.O. 3250(E) dtd. 20th July. 2022. PP requested Public Hearing exempted for rolling mills regularization projects As per Gazette of India Notification dtd. 20th July, 2022 as this unit is located in the Industrial area. The Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's as annexed as annexure “D”:-

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

1. Compliance of earlier issued CTE/CTO conditions issued by MPPCB in the EIA report.
2. Furnish details of CO₂ emission & quantification from different sources as DG sets, vehicles movements etc. and their management plan w.r.t. carbon foot print shall be studied and discussed in EIA report.
3. In EIA study the mode of transportation, storage of fly ash, all raw materials and products should be discussed along with their impacts.
4. Transportation plan & traffic management plan should be discussed in the EIA report.
5. Inventory of all sensitive receptors in 2 Km & 5 Km around the mine.
6. Input data of modeling should be addressed in EIA along with this all back up calculation.
7. Onsite pictures of monitoring and survey along with date and time on photographs should be attached with the EIA report.

15. Case No 9921/2023 Shri PRAKUL PATIDAR, Lessee, R/o- 115, Village Rasulpur Jaora, Tehsil- Jaora, District- Ratlam, M.P Prior Environment Clearance for Sarwanikhurd Stone Quarry in an area of 2.00 Ha. (Stone – 10000 m³/year & M-Sand – 5000 m³/year) at (Khasra No. 173 (Govt.) Village Sarwani Bant Tehsil Ratlam District Ratlam (M.P.)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 173 (Govt.) Village Sarwani Bant Tehsil Ratlam District Ratlam (M.P.) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रकुल पाटीदार (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन.सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 903 दिनांक 27/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है खदान के दक्षिण दिशा में 97 मीटर की दूरी पर एक प्राकृतिक नाला है एवं उत्तर दिशा में 479 मीटर पर नदी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम ने पत्र क्रमांक 903 दिनांक 27/04/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के दक्षिण दिशा में 97 मीटर की दूरी पर एक प्राकृति नाला है एवं उत्तर दिशा में 479 मीटर पर नदी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. चूंकि खदान क्षेत्र में पौधारोपण करना संभव प्रतीत नहीं होता अतः पौधारोपण की वैकल्पिक व्यवस्था ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।
3. यदि आस-पास का क्षेत्र नीलगाय का विचरण क्षेत्र हो तो पौधारोपण में ऐसी प्रजाति का चयन करे जो नीलगाय से प्रभावित न हो ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

16. Case No 9615/2023 Shri Ajay Pathak Partner, M/s Maa Infratech, Vijay Nagar, Sector No.-3, District-Gwalior (MP)-474012, Prior Environment Clearance for Upcha Stone & M-Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone-25000 & M-sand-25000 Cum per annum) (Khasra No. 927), Village- Upcha, Tehsil-Vijaypur, District-Sheopur (MP)

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 927), Village- Upcha, Tehsil-Vijaypur, District-Sheopur (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 627वीं बैठक दिनांक 03/03/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पाठक (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

आईएनसी., बड़ौदरा, (गुजरात)उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 11038 दिनांक 11/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर पूर्वी दिशा में 100 मी. पर आबादी, पूर्व दिशा में 41 मी. पर, दक्षिण-पूर्व में 50 मी. पर एवं 308 मी. पर शेड स्थित है। उत्तर-पश्चिम में 292 मी. पर मौसमी नाला एवं एक पूर्व उत्तर दिशा में 104 मी. पर कच्चा रोड है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। मौसमी नाले के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक भी प्रस्तावित किये गये हैं। उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्र०. 25 एवं सरल क्र०. 10 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम. सेंड – 25,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.93 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.61 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर.	राशि (रु.में)
उपचा के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार स्वास्थ्य केंद्र में उपयोग हेतु सामग्रीधुपकरण उपलब्ध कराये जावेंगे।	80,000/-

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1550 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- पीपल,चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, बरगद, करंज आदि।	700
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- करंज, नीम, चिरोल, पीपल, सिस्सू, कदम, पुत्रंजीवा आदि।	200

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

3	ग्राम उपचा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि। (पूर्ण सुरक्षा सहित)	200
4	ग्राम उपचा के नजदीक स्थित ग्राम पंचायत में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, मोलश्री, सिस्सू, बरगद, पीपल, कचनार, कदम, चिरोल आदि। (पूर्ण सुरक्षा सहित)	150
5	ग्राम उपचा एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- मुनगा, आम, जामुन, सीताफल, अनार, निम्बू, अमरुद, कटहल, आमला आदि।	1300
योग			1550

सिया के पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04/04/23 के द्वारा खदान पहाड़ी पर स्थित है और अभी इस पहाड़ी पर कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। खदान के उत्तर दिशा में आबादी, पूर्व व दक्षिण-पूर्व पर कुछ शेड स्थित है तथा उत्तर दिश में कच्चा रोड़ है। गूगल इमेज से साफ दिखता है कि खदान से लगी हुई पहाड़ी के नीचे आबादी तथा यह एक वर्जन पहाड़ी की श्रृंखला है, जिसमें खनन कार्य होने से आबादी को प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं का भी सामना करना होगा। इसके अलावा पहाड़ी के खनन कार्य से Subsidence की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसका पूरी पहाड़ी की श्रृंखला में पर्यावरणीय प्रभाव पड़ने से बहुआयामी यूनिक माउटेन ईको सिस्टम प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा खनन कार्य से आसपास के भू-दृश्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहेगी। प्रकरण की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्रकरणों में एक बार खनन कार्य शुरू होने से पूरी पहाड़ी की श्रृंखला पर आने वाले समय में खनन कार्य बढ़ने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसका आबादी पर पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा। उपरोक्त वस्तुस्थिति के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया गया है।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

प्रकरण समिति की 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पाठक (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, (गुजरात) उपस्थित हुए।

उपरोक्त प्रकरण में जैसा कि सिया ने उल्लेख किया है कि यह एक वर्जन पहाड़ी है। गूगल इमेज में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह वर्जन पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी के उत्तर पूर्व में पहाड़ी के ऊपर ही लोगो ने अपने मकान जगह-जगह बना रखे हैं। नीचे से ऊपर तक (काफी संख्या में) निश्चित रूप से इस प्रकार से आबादी बसना किसी पहाड़ी पर पहाड़ के श्रृंखला के दृष्टिकोण से एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से ऐसी बासाहट उपयुक्त नहीं कही जा सकती। खनन कार्य बासाहट के विपरीत

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

दिशा में एवं ढाल के दूसरी तरफ भी है जिससे कि यहां पर पानी बहकर आबादी के तरफ आने की संभवना नहीं प्रतीत होती । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो अक्षांस-देशांस दिये गये थे वे अक्षांस-देशांस खनिज अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 1836 दिनांक 02/3/23 के द्वारा बताया कि वे सही है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति से निवेदन किया कि सिया द्वारा उल्लेखित पर्यावरणीय संवेदनशील बिंदुओं को स्पष्ट करने हेतु कुछ समय दिया जावे । समिति ने परियोजना प्रस्तावक का निवेदन को स्वीकार करते हुए 15 दिवस का समय दिया जाता है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 29/05/23 को उपलब्ध जानकारी अपलोड की गई । अपलोड की गई जानकारी को आज दिनांक 07/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया ।

PP submitted following query reply wrt to the SEAC meeting 647th dated 29.05.2023.

- PP submitted mine lease is situated at the foothill of the hillock. The mine lease area is at distance of ~160m from the hillock range which starts from the average RL of 300m but here the highest RL of our mine lease area is 261m henceforth we are at the sufficient distance from the hillock range. Google satellite image (3D) PP submitted during presentation.
- As habitation is there in the northern side of the ML area at more than 100m from the ML area in protection of which following the NGT O.A no 304/2019 we have proposed the mining through rock breaker and no blasting will be carried out at ML area as per the mining plan which is approved by the Directorate of geology & mining Regional Office Gwalior vide letter no 1158/ M.P. SEL 189/F.no 01/2022 dtd 11-17-2022. However the sheds which seems to be appears in the eastern side & western side of the ML area are type of store room used for keeping the agriculture machineries, fodder etc not for any living purpose. We have also attached notarized affidavit from the Shed owners stating the same. We have proposed non-mining zone upto 100m from these sheds at both side indicated in the EMP map and is attached in below slide, additionally we like to inform that these structures are encroached on the government land including the encroachment on foothill of the hillock approx 5000-6000 sq. mt, hence the hillock range is no more virgin hillock range due to these encroachment.
- As this is M-sand quarry but considering the protection of nearby habitation & sensitivity We commit that crusher/M-sand plant will not be installed within the ML area and the M-sand plant/crusher will be installed away from the habitation outside the mine lease area which will protect habitation from the dust emission due to crushing of stone by crusher. The crusher/M-sand plant will be installed at Khasra no

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

921,922 923 & 926 (Private land) at area of 1.35 ha. on flat land not on the hill which is approx. 220m from our ML area and about 400m from the habitation, PP submitted/ shown the agreement for the same by the land owner for giving the consent for the installation of crusher is attached at slide below.

- As a kaccha road is there in the eastern side of the ML area which is more than 50m from the ML area and as no blasting will be carried out mining and the mining will be carried out through rock breaker.
- We have also proposed the curtaining of the ML area by MS sheet of 4m height in northern, eastern and western side of the ML area to avoid the emission of the dust towards the habitation and kachha road due to mining operations which is indicated in the EMP map and is attached at above slides.
- To mitigate the emission of the dust during the mining activity, we'll perform dust suppression and 1.60 KL/day water is proposed for the dust suppression which will minimize the emission of the dust at the nearby land & habitation.
- We will also plant the saplings with thick leaves towards the side of the habitation covering the periphery of about 500m and at the area of 2000 sq.mt where the proposed approach road lies which act as a protecting wall for the habitation & minimize the effect of mining operation towards the habitation.
- Additionally we'll left non-mining zone upto 100 m from the sheds at both the eastern & western side of the ML area so the unused area at these both corners of the mine lease will extend which will act as barrier for the flying rocks and as a protective wall for the nearby land. We have also indicated the same in the satellite image and also in the EMP map attached in the presentation.
- As the mining operation is at opposite direction of the habitation and also between the habitation & the minable area, a ridge wall with increased slope is there which will act as a protective wall for the habitation in northern side (indicated in Google satellite image). Although the slope is not towards the habitation hence there is not any chance of water flowing towards habitation, however we have proposed 4 nos settling tanks which are between point no 3-2, 1- 6, 3-4 & 5-6 which is indicated in the attached EMP map attached in above.
- We have also carried out the surface water runoff calculation (attached in below slides) in which it is justified that the proposed settling tanks having the capacity of 350KL which is are sufficient to bear the surface runoff water from the ML area and no excess water will overflow towards the habitation.
- If we talk about the subsidence issue due to mining at our mine lease: We would like to address that the average surface level of the area is 228m and the RL of our mine lease is 263m and the proposed ultimate depth of mine pit is 22m, here is the elevation difference of 13m still left in reaching the ground surface level. However

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

the hillock range is away from our mine lease at the distance of more than 160m in southern side of our ML area.

- We commit to maintain the proper benches as per the approved mining plan and will maintain the proper slope so as to avoid the development of deep pit.
- Our mine lease is situated at the foothill of the hillock and as we have addressed that the average ground surface level is 228m and the RL at our mine lease is 263m and the ultimate depth of mining is 22m & the ground water table is at 40-50m from the ground level hence forth our proposed ultimate depth is much more above from the ground water table and there is no chances of any disturbance to the ground water table therefore there no chances of subsidence due to disturbance of the ground water table.

Here as per the submitted mining plan which is approved by the Directorate of Geology & Mining Regional Office Gwalior vide letter no 1158/ M.P. SEL 189/F.no 01/2022 dtd 11-17-2022 no blasting will be carried out at the ML area and the mining will be carried out using rock breaker.

PP submitted that due to the above facts the chances of subsidence of the hillock range is very less and no chance of disturbing the hillock range as our ML area is far away from the hillock range and we'll commit to maintain the necessary mitigations as addressed. Henceforth there's not any disturbance to the hillock range as result theirs is very rare chances of any effect on the mountain ecosystem due to the mining operation mentioned area. Eexample case no. 8736/2021 (Virgin hill & habitation all around ML area) Distt: Chhatarpur), 8706/2021(Virgin hill & habitation all around ML area), 8323/2021, 8486/2021.

यद्धपि उक्त क्षेत्र का स्वास्थ्य एक बड़े लैंड स्केप के रूप में है पर इसी क्षेत्र में मानवीय बसाहट भी स्थित है जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तथा खनन् कार्य से जो विपरीत प्रभाव पड़ने की संभवना है उस हेतु कई प्रावधान किये गये है । प्रश्न यह है कि सभी प्रावधान समय पर क्रियान्वित हो जो सामान्यतः देखने में नहीं पाया जा रहा है । अतः प्रभावी क्रियान्वयन एवं सावधानी तथा प्रत्येक छः माह पर प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर स्वीकृत की अनुशंसा सशर्त दी जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वांछित जानकारी, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम. सेंड – 25,000 मी³ प्रति वर्ष ।

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.32 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.76 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर.	राशि (रु.में)
उपचा के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार स्वास्थ्य केंद्र में उपयोग हेतु सामग्री उपकरण उपलब्ध कराये जावेंगे ।	80,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-
- 5.

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1	बैरियर जोन में (प्रथम वर्ष)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, बरगद, करंज आदि ।	700
2-	उत्खनिपट्टे के उत्तर दिशा में आबादी की ओर 500 मीटर की लम्बाई में लगभग 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, बरगद, करंज आदि ।	700
3.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, नीम, चिरोल, पीपल, सिस्सू, कदम, पुत्रंजीवा आदि ।	200
4	ग्राम उपचा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि । (पूर्ण सुरक्षा सहित)	50
5	ग्राम उपचा के नजदीक स्थित ग्राम पंचायत में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, मोलश्री, सिस्सू, बरगद, पीपल, कचनार, कदम, चिरोल आदि । (पूर्ण सुरक्षा सहित)	150
6	ग्राम उपचा एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- मुनगा, आम, जामुन, सीताफल, अनार, निम्बू, अमरुद, कटहल, आमला आदि ।	1300
योग			2400

17. प्रकरण क्रमांक 9047/2022 - मेसर्स श्री मां नर्मदा एग्रोटेक एवं इन्फ्रस्टाचर लि., ग्राम धुरेरी तहसील देपालपुर जिला इंदौर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1/1/1, 1/1/1/2, 1/1/1/3,

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

1/2/1, 1/2/2 रकबा 01.90 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन- 14,700 मी.³ ग्राम धुरेरी तहसील देपालपुर जिला इंदौर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1/1/1, 1/1/1/2, 1/1/1/3, 1/2/1, 1/2/2 रकबा 1.90 हेक्टेयर, ग्राम धुरेरी तहसील देपालपुर जिला इंदौर (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 556वीं दिनांक 02/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 641वीं बैठक दिनांक 03/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

आज दिनांक 29/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अजय मोदी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार शासकीय भूमि पर आवंटित है, प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान की उत्तर दिशा में 90 मीटर पर पक्का रोड़ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर दिशा में 90 मीटर पर रोड़ होने के कारण 10 मीटर का सेट बैक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है । Bamboo Agro Industry sheds – 486 Mt. North West side मे स्थित है तथा अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है प्रश्नाधीन खदान की उत्तर दिशा में 90 मीटर पर पक्का रोड़ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर दिशा में 90 मीटर पर रोड़ होने के कारण 10 मीटर का सेट बैक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है। । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र की स्वाईल प्रोफाईल प्रस्तुत नहीं कर सके अतः समिति ने चर्चा कर यह निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत की जाये।

- खदान क्षेत्र के बेरीयर जोन में तीन या चार स्थानों में ट्राईल पिट खोद कर स्वाईल प्रोफाईल प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 03/06/23 को उपलब्ध जानकारी अपलोड की गई । अपलोड की गई जानकारी को आज दिनांक 07/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया ।

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान धूल मिट्टी न उड़े इसके लिये जल छिड़काव की व्यवस्था, वृक्षारोपण, सड़को की मरम्मत, आंगनबाड़ी में बच्चों के लिये खेल उपकरण उपलब्ध कराये जाने की मांग इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 48 के सरल क्रमांक 92 पर दर्ज है। चूंकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के अक्षांश-देशांश दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन योजना में दिये गये अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 14,700 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 12.56 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.42 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रु.में)
ग्राम धुरेरी के आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए खेल के उपकरण दिए जायेंगे	20,000
ग्राम धुरेरी ग्रामीणों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी	80,000
ग्राम के रोड की मरम्मत की जाएगी	50,000
कुल	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2300 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु	390

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

		आदि।	
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 0 1 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	130
3	खदान पट्टे के पश्चिम दिशा में 90 मीटर की दूरी पर खनिज निकास रोड है, इस रोड के एक तरफ 4 की मीटर ई तक दो लाइनों में लम्बालगायेंगे	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि (पूर्ण सुरक्षा सहित)	200
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	1580
			योग 2300

18. Case No 9644/2022 Shri Himanshu Meena, Partner, M/s Euphoria Mines & Minerals, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, Bhopal (MP)-462013. Prior Environment Clearance for Ghatpipariya-3 Sand Quarry on Narmada River in an area of 08.00 ha. (128949 Cum per annum) (Khasra No. 306), Village- Ghatpipariya-3, Tehsil-Baraily, District-Raisen (MP).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 306), Village- Ghatpipariya-3, Tehsil-Baraily, District-Raisen (MP). 8.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 621वीं दिनांक 20/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 07/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 428 दिनांक 31/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है एवं इनका क्षेत्रफल 5.00 हे. से अधिक होने के कारण यह प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है तथा खनन मैनुअली किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक ने नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान के विवरण में पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-05 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-1,44,000 घनमीटर उल्लेखित है तथा टॉर 1,28,949 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत) से कम है।

इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, रोजगार, स्पीड ब्रेकर, गांव के लिये पीने का पानी की व्यवस्था इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। यदि वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत/असहमति किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव किया जावेगा एवं तत्संबंध में राशि ग्राम पंचायत को दी जायेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी. अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 1,28,949 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 20.56 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 05.49 लाख प्रति वर्ष।
3. रेत खनन का प्रकरण नर्मदा नदी में होने के कारण सिर्फ मैनुअल माईनिंग (Only Manual Mining) की जाये।

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण प्रथम र्वा (दिनांक 30.6.2023 तक) में किया जावेगा। अथवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण योजना में होने वाले व्यय को संबंधित ग्राम पंचायत अथवा वन विभाग को निर्धारित राशी 5.31 और 10 परसेंट रख रखाव के लिए 53,150/- राशि प्रदान की जायेगी । यदि ग्राम पंचायत द्वारा पौधारोपण कार्य में असहमति प्रकट की जाती है तो परियोजना प्रस्तावक अन्य सक्षम संस्था (जैसे स्थानीय पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था) को वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा सोपा जा सकता है तथा सी.ई. आर. की राशि यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन अवधि में पूर्ण की किये जाने की स्थिति में नहीं तो उक्त राशि को ग्राम पंचायत के खाते में जमा करा दी जाये तथा उक्त दोनों कार्यों (वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर.) की क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर खनिज विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावे:-
6. वृक्षारोपण हेतु समिति द्वारा निम्न सुझाव दिये जाते हैं:-
 - अ. कुल रोपित वृक्ष - 9600 न0.
 - ब. परियोजना प्रस्तावक संबंधित वन मंडलाधिकारी से सहमति प्राप्त करेंगे । सहमति प्राप्त ना होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं या स्थानीय ग्राम सभा/ वन विकास समिति/पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य प्रथम वर्ष में संपादित किया जावेगा। यदि खनन अवधि में वृक्षारोपण संभव नहीं हो तो वृक्षारोपण हेतु समस्त राशि संबंधित ग्राम सभा/वन विकास समिति को जमा करके संबंधित जिला खनिज अधिकारी को सूचित करेगा।
वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के समस्त कार्यों के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर खनिज विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावे:-
7. पौधारोपण का कार्य निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास) 2,000(4-5 पंक्ति - कटंग बांस) 2315(6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, जंगल जलेबी, लसोड़ा एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां) 1000(5315

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

बिंदु क्रमांक 1 वन विभाग द्वारा रोपण किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा स्वीकृति प्रोजेक्ट अनुसार			
2	घाटपिपरिया 3, माछा और अजेरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	4000
3	परिवहन मार्ग में (350m)	नीम, पीपल, चिरोल, जंगल जलेबीए, आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	235
4	ग्राम घाटपिपरिया 3 में प्राथमिक विद्यालय में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक, नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि।	50
कुल			9600
बिंदु क्रमांक 2,3,4 रोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयंम्, ग्राम पंचायत या स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जावे ।			

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.30 लाख तथा प्रस्तावित सभी कार्य खनन अवधि समाप्ति के पूर्व में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
प्राथमिक विद्यालय घाटपिपरिया-03 में प्रिंटर सहित 01 कम्प्यूटर एक टेबल और एक कुर्सी उपलब्ध कराने के लिए।	50,000 / -
घाटपिपरिया-03 गांव में नया हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना की जाएगी।	60,000 / -
ग्राम घाटपिपरिया-03 में वर्ष में दो बार स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था	20,000 / -
योग	1,30,000 / -

समिति द्वारा सुझाये गये बिंदु जिनपर सिया द्वारा विचार किया जाना प्रस्तावित :-

समिति का सुझाव है कि समरूप प्रकरणों में जो एक बड़ी पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा हो ऐसी पहाडियो पर कोई भी खनन् कार्य न किया जावे इस हेतु एक नीतिगत निर्णय लिया जाना उपयुक्त होगा पूर्व में कई खनन् कार्य जो स्वीकृत हुए है, यद्यपि सभी संवेदनशीलता को ध्यान में रख के आवश्यक उपाय का प्रावधान समिति द्वारा दिया गया था जिससे कि पर्यावरणीय घटको को न्यूनतम क्षति खनन् कार्य से हो। परन्तु खनन् कार्य से खनिज संपदा एवं स्थानीय रोजगार तथा राज्य शासन का राजस्व भी जुड़ा हुआ विषय है । अतः किस स्वरूप की पहाड़ी श्रृंखलाओ को लैंड स्केप के अंतर्गत लिया जावे उनके विस्तार एवं अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे वन्यप्राणी विचरण क्षेत्र, नदी नाले के क्षेत्र, भूमि मृदा की संरचना जैसे बिंदुओ को ध्यान में रखा जावे तथा खनन् कार्य हेतु स्वीकृति न दी जावे, इस हेतु

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 जून 2023

नीतिगत निर्णय सिया स्तर से विषय विशेषज्ञों से राय लिया जाना उचित होगा । ऐसे चयनित पर्वत श्रृंखलाओं से सूचिबद्ध किया जाकर प्राथमिक स्तर पर ही इनका परीक्षण कर लिया जावे तथा इस समिति को पुनः तकनीकी परीक्षण की पुनः आवश्यकता ही न पड़े ।

पूर्व में कई प्रकरणों में ऐसे प्रकरण सामने आये कि जिसमें इन बिंदुओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के आस-पास के रहवासी के दृष्टिकोण से आवश्यक संरक्षण के उपाय समिति द्वारा प्रस्तावित किये गये थे उसी क्रम में यह प्रकरण भी है जिसमें आपके द्वारा उठाये गये बिंदुओं पर समिति द्वारा आवश्यक उपाय सुझाये गये थे यदि किसी वर्जन पहाड़ी पर खनन कार्य नहीं किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो इस संबंध में एक नीतिगत निर्णय भविष्य हेतु लिया जाना होगा । प्रकरणों के तकनीकी परीक्षण के पूर्व ही उस पर यथोचित निर्णय लिया जाना उचित होगा ।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 जून 2023

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 जून 2023

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 जून 2023

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 जून 2023

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 जून 2023

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 जून 2023

30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 जून 2023

- an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 07 जून 2023

34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिपल जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

649वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 जून 2023

नोट 4 :- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण । जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बाँस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर